VISION IAS

www.visionias.in

04 JUL 2022

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1821)

Name of Candidate	जतिन पाराशर		
Medium Eng./Hindi	हिन्दी	Registration Number	674865
Center	मुखर्जी नगर	Date	4/07/22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. With adequate arguments and examples, elaborate your views on whether interest and pressure groups in India are undermining democracy or strengthening it. **(150 words) 10**

पर्याप्त तर्कों और उदाहरणों के साथ, सविस्तार अपने विचार व्यक्त कीजिए कि क्या भारत में हित समूह और दबाव समूह लोकतंत्र को दुर्बल कर रहे हैं या इसे सुदृढ़ कर रहे हैं।

हित समूह और दबाव समूह, मुद्दे आधारित ऐसे संगठन होते हैं जो अपनी माँगों की पूर्ति हेतु सरकार (लोकसेवकों) पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं।

दबाव व हित समूहों द्वारा लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण

(1) क्षेत्रक की मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना

ये समूह अपने क्षेत्र विशिष्ट माँगों को जैसे:- कर सुधार, विनियमन सुधार आदि सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

(2) राजनीतिक भागीदारी का अवसर

नागरिकों को बिना किसी दल की सदस्यता के राजनीतिक भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं।

(3) सुभेद्य वर्गों की माँगो को उठाना

LGBTQ+ के मुद्दों को, महिलाओं के मुद्दों को प्रस्तुत करना।

जैसे:- नाज़ फाउंडेशन द्वारा धारा-377 के विरुद्ध आंदोलन।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ सरकार पर जवाबदेही व पारदर्शिता हेतु दबाव

किसान-मजदूर शक्ति संगठन के प्रयासों के पश्चात् ही RTI अधिनियम पारित किया गया।

लोकतंत्र को दुर्बल करने में भूमिका

① अल्पसंख्यक हितों को बढ़ावा

ये विशिष्ट रूप से अपने क्षेत्रक की माँगों को प्रस्तुत करते हैं। जिससे अल्पसंख्यक हित को बढ़ावा की आशंका।

② जवाबदेहिता का अभाव

चुनावों में भाग नहीं लेते अतः जनता के प्रति अनुत्तरदायी।

③ हिंसा आदि हथों का सहारा

लोकतांत्रिक माध्यमों के स्थान पर धरना-प्रदर्शन, हिंसा आदि माध्यमों का प्रयोग।

④ नागरिक स्वतंत्रताओं में बाधा

धरना-प्रदर्शन, जाम की राजनीति से आम नागरिकों के आजीविका, स्वस्थ पर्यावरण, आवागमन के अधिकार में बाधा उत्पन्न होती है।

हित व दबाव समूह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं यह शासन की नीतियों के समर्थन/विरोध में स्वस्थ जनमत का निर्माण करते हैं यद्यपि इन्हें अपनी प्रक्रियाओं व तरीकों में जवाबदेही व पारदर्शिता लाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. The Representation of People Act holds the key to improving the electoral system in India. Discuss the important contemporary issues in this context.
(150 words) 10

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भारत में निर्वाचन व्यवस्था में सुधार की कुंजी समाहित है। इस संदर्भ में, महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों की विवेचना कीजिए।

चुनावों के संचालन, मतदान, मशीनरी दलों व ~~मत~~ उम्मीदवार संबंधी विभिन्न प्रावधानों का वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मिलता है।

भारत में निर्वाचन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

- धन-बल का बढ़ता प्रयोग
- दल-बदल की बढ़ती घटनाएँ
- राजनीति का आपराधीकरण (50% सांसदों पर आपराधिक मामला)
- आचार संहिता की अवैधानिक प्रकृति
- पेड-न्यूज; Hate speech जैसे बढ़ते मुद्दे

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व निर्वाचन व्यवस्था में सुधार

(1) धन-बल के बढ़ते प्रयोग के विरूद्ध

- रिश्वत लेने देने को व इसके तहत अपराध घोषित किया जाये
- धारा - 58(B) में संशोधन द्वारा धन के प्रयोग होने पर मतदान रद्द करने का अधिकार शामिल हो
- पेड न्यूज ~~के~~ संस्कृति पर लगाम लगाने का प्रावधान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② आपराधीकरण रोकने हेतु

- गम्भीर प्रकृति के अपराध में मामला दर्ज होने पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध
- ऐसे लोगों को टिकट न देने की बाध्यता (दलों पर) लगाई जाए

③ आदर्श आचार संहिता का ~~संहिताकरण~~ विधिकरण व उसको अधिनियम के तहत लाया जाये।

④ दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को प्रदान की जाए। [आदेश उल्लंघन पर]

⑤ हेट स्पीच, Fake news, जैसे मामलों पर निर्णय लेने हेतु निर्वाचन आयोग को सशक्त किया जाये।

⑥ राजनीति उम्मीदवारों के मामलों पर तीव्र निर्णय हेतु अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों में बेंच गठित की जाए।

भारत में निर्वाचन सुधार का मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में सुधार से जुड़ा है। जो जिसमें सुधारों की तत्काल आवश्यक है ताकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बनाया जा सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. The scheme of lateral entry into civil services in India raises more issues than it proposes to solve. Discuss. **(150 words) 10**

भारत में सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश की योजना अपेक्षित समस्या समाधान की तुलना में अधिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। चर्चा कीजिए।

सिविल सेवा में होने वाली गैर-सरकारी तथ्यों की कमी तथा विशेषज्ञता के अभाव की समस्या के समाधान हेतु सिविल सेवा में पार्श्व प्रवेश की योजना प्रारंभ की गई है।

सिविल सेवा में पार्श्व प्रवेश

- क्षेत्र विशेषज्ञों की 5 वर्षों हेतु नियुक्ति
- प्रक्रिया का आयोजन UPSC के तहत
- सीधे उच्चस्तर (सचिव) पर नियुक्ति

पार्श्व प्रवेश से समस्याओं का समाधान

① **सिविल सेवकों की सामान्यता**

भारत में सिविल सेवकों को सामान्यतः सामान्यज्ञ माना जाता है व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त नहीं होती अतः इसक समस्या का समाधान पार्श्व प्रवेश द्वारा।

② **तकनीकी व आर्थिक मुद्दों में बढ़ती जटिलता**

पर्यावरण - जलवायु असंतुलन, संगठित अपराध आदि

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

जटिल मुद्दों ~~का समाधान इसके अलावा~~ पर विशेषज्ञ राय उपलब्धता में वृद्धि।

③ सिविल सेवाओं की कमियाँ

धीमी, लालफिताशाही युक्त व कार्पोरेट गुणों के अभाव युक्त होने के आरोप भारतीय सिविल सेवा पर चूंकि लेटरल एन्ट्री द्वारा आने वाले लोक सेवक निजी क्षेत्र से आऐंगे अतः वे निजी क्षेत्र की प्रतिद्वंदिता, तेजी व ग्राहक केन्द्रिता के गुण भी लायेंगे।

योजना से समस्याऐं

① पार्श्व एण्ट्री प्राप्त लोकसेवकों की प्रतिबद्धता पर प्रश्न।

② यद्यपि वे विषय विशेषज्ञ होंगे पर नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों के विशेषज्ञ नागरिकों के मध्य कार्य करने वाले लोकसेवक होते हैं।

③ निजी क्षेत्र में कार्य स्वयं के अधिकतम लाभ हेतु किये जाते हैं किन्तु सरकार की कार्यप्रणाली जनता के अधिकतम लाभ की होती है।

④ यह योजना आम सिविल सेवक व पार्श्व एण्ट्री पश्चात् आने वालों के मध्य संघर्ष उत्पन्न कर सकती है।

स्पष्ट है कि इस योजना के लाभ इसकी समस्याओं की संभावना पर श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं, सामान्य सिविल सेवकों पर विश्वास दिलाते हुए सरकार को इस पर आगे बढ़ना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. The National Digital Health Mission (NDHM) has the potential to bring a new revolution in India's health sector in multiple ways. Explain.

(150 words) 10

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रक में कई तरह से एक नई क्रांति लाने की क्षमता है। व्याख्या कीजिए।

नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित Health Stack के क्रियान्वयन में भारत द्वारा राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया है।

मिशन के उद्देश्य

- स्वास्थ्य क्षेत्र का डिजीटलीकरण
- स्वास्थ्य क्षेत्र की अवसंरचनाओं को जोड़ना
- भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण

मिशन में स्वास्थ्य क्षेत्रक में नई क्रांति लाने की क्षमता

① दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच

मिशन के तहत स्थापित टेली मिडीसिन, Digital Doctors आदि माध्यमों से।

② ~~स्वास्थ्य~~ out of Pocket स्वास्थ्य व्यय को कम करना

मिशन के तहत ~~मरीज~~ प्रत्येक व्यक्ति की HealthID व डॉक्टरों की सूची डिजीटल की जाएगी जिससे व्यक्ति अपने लिए सर्वश्रेष्ठ व किफायती डॉक्टर चुन सकेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- व्यक्ति की HealthID में उससे जुड़ी संबंधित सभी जानकारियां व पुरानी जाँचें उपलब्ध होंगी जिन्हें पुनः करवाने पर व्यय में कमी आयेगी।

③ मानव संसाधन की कमी से निपटना

दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की अनुपलब्धता को Digital सुझाव आदि माध्यमों से पूरा किया जाएगा।

④ स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित Data की कमी दूर

यद्यपि भारत में स्वास्थ्य संबंधी आँकड़े उपलब्ध किंतु उनके Interlinkage का अभाव है इसकी सहायता से नई बीमारियों का पता लगाने व अन्य प्रकार के Data संबंधी लाभ होंगे।

⑤ स्वास्थ्य क्षेत्रक की मनमानी पर रोक

भारत में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यधिक महँगे उपचार, अनियमित लाभों व जैसी समस्याओं से ग्रस्त। योजना के माध्यम से इस पर निगरानी में सहायता होगी।

⑥ इसके अतिरिक्त सुभेद्य वर्गों को स्वास्थ्य अवसंरचना में शामिल करना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी जैसे लाभ भी इससे जुड़े हैं।

भारत को वित्तीय निवेश की कमी, अशिक्षित मानव संसाधन का अभाव तथा डिजीटल डिवाइड जैसी समस्याओं का समाधान खोजते हुए इस योजना को तीव्रता से आगे बढ़ाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Explain the rationale behind the creation of a Social Stock Exchange in India. Do you think this move would boost social impact investing in the country? **(150 words) 10**

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे निहित तर्क की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस कदम से देश में सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा?

भारत में सामाजिक सुभेद्य वर्गों के हितों हेतु वित्त की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से सेबी (SEBI) के विनियमन के तहत सोशल स्टॉक एक्सचेन्ज की स्थापना की गई है।

इसके सृजन के पीछे निहित तर्क

① सामाजिक हित वाली योजनाओं में ~~निवेश~~ वित्त की कमी को पूरा करना।

② विदेश से प्राप्त होने वाले अनुदान को ~~एक~~ व्यवस्थित रूप से विनियमित करना (हाल ही में विदेशी अभिदाय अधिनियम में किए गए सुधार के परिप्रेक्ष्य में)

③ सामाजिक क्षेत्रक में दान के इच्छुक व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना।

④ स्टॉक के माध्यम से किया गया निवेश प्राप्तकर्ताओं पर सही उपयोग की जवाबदेही रखेगा।

⑤ भारत में उस क्षेत्र में हो रहे अबैंध धन के स्थानांतरण व उपयोग पर नियंत्रण करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(विभिन्न NGO का कर अपवंचन हेतु उपयोग)

इसके द्वारा निवेश को प्रोत्साहन

① निवेश करने इच्छुक किन्तु उचित माध्यम तलाशने वाले व्यक्तियों की समस्या का समाधान।

② विदेशी वित्तपोषण की सम्भावनाओं में वृद्धि।

③ पारदर्शी प्रक्रियाओं के पालन से निश्चित निवेश को प्रोत्साहन।

④ दीर्घकालीन वित्तपोषण में सहायता।

योजना निश्चित ही सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहित करेगी किन्तु सरकार को यह भी विनियमित करना होगा कि प्राप्त धन का किसी अन्य क्षेत्र में उपयोग न होने पाये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Highlight the issues associated with frequent transfers of civil servants. Also, throw light on the views of various committees and Supreme Court directives in this regard. **(150 words) 10**

सिविल सेवकों के बार-बार स्थानांतरण से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इस संबंध में विभिन्न समितियों के विचारों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को रेखांकित कीजिए।

सिविल सेवा राज्य की स्थायी कार्यपालिका होती है जो शासन की नीतियों को निरंतरता प्रदान करती है।

किन्तु वर्तमान में देखा गया है कि विभिन्न कारणों से चुनाव पूर्व, नई सरकार के गठन पर, मंत्रियों व राजनेताओं के विरोध पर सिविल सेवकों बार-बार स्थानांतरण किये जाते हैं।

बार-बार स्थानांतरण के कारण

- राजनीतिक तरफदारी से मना करना
- दण्ड स्वरूप
- पसंद के सिविल सेवकों की अत्यावश्यक मंत्रालयों में नियुक्ति
- भ्रष्टाचार से इन्कार करना
- नागरिकों से समीपता

बार-बार स्थानांतरण के कारण समस्याएँ

① नीति क्रिया-न्वयन में बाधा
बार-बार स्थानांतरण से नीति की निरंतरता प्रभावित होती है तथा क्रियान्वयन में बाधा आती है।

② इसके कारण सिविल सेवक किसी विशेष क्षेत्र में

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विशेषज्ञता प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं जैसे: स्वास्थ्य विभाग से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण।

③ नवीन जिले/विभाग की समस्याओं को तह तक पहुंचने समय की आवश्यकता, इसके बिना नीतियों के अलक्षीकरण की समस्या उत्पन्न होती है।

④ सिविल सेवा के राजनीतिक तटस्थता के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह स्थापित होते हैं।

⑤ सिविल सेवक पर मानसिक दबाव में वृद्धि होती है जिससे वह स्वयं अपनी समस्याओं में उलझ जाता है जिससे दक्षता में कमी आती है।

इस संबंध में होता समिति, सर्वोच्च न्यायालय, II-ARC ने निम्न सुझाव दिये हैं-

① 2 साल की निश्चित नियुक्ति।

② स्थानांतरण, पदस्थापना आदि मामलों हेतु 'राष्ट्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण' की स्थापना।

③ मतदान पूर्व आवश्यक स्थिति में ही स्थानांतरण

④ स्थानांतरण में राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए।

सिविल सेवा, भारतीय प्रशासन के क्रियान्वयकर्ता हैं बार-बार स्थानांतरण से प्रशासन प्रभावित होता है तथा अंतिम रूप से नागरिक परेशान होते हैं अतः इस पर रोक लगाना अत्यावश्यक है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. It is often argued that the implementation of Forest Rights Act has so far been tardy and ineffectual. Discuss. **(150 words) 10**

प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहा है। चर्चा कीजिए।

जनजातियों व आदिवासियों को वनों पर उनके पारम्परिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से वन अधिकार अधिनियम-2006 पारित किया गया।

अधिनियम द्वारा प्रदान किये गये अधिकार

- भूमि का अधिकार (4 हेक्टेयर)
- आजीविका का अधिकार
- संरक्षण व प्रबंधन का अधिकार
- वनोपज संग्रहण का अधिकार

अधिनियम का धीमा और निष्प्रभावी क्रियान्वयन

(1) उड़ीसा, झारखण्ड, जैसे राज्यों में अभी भी विशाल आबादी वन अधिकारों से वंचित है।

(2) अधिकार प्रदान का अधिकार जिला प्रशासन को दिये जाने से भूमि अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है।

(3) वनोपज संग्रहण को लेकर वन-विभाग व आदिवासी समुदायों में टकराव विद्यमान है।

(4) अधिकारों की सीमा राजस्व ग्राम तक करने से अधिनियम निष्प्रभावी प्रतीत होता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) वन विभाग द्वारा पारम्परिक संरक्षण के अधिकार प्रदान करने में लापरवाही बरती जाती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अधिनियम के संबंधित फैसले ने इस मामले को और अधिक पेचीदा कर दिया था। जिससे कार्यान्वयन प्रभावित हुआ किन्तु विभिन्न राज्यों (मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि) ने अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी दिखाई है जिसका लाभ भी नजर आने लगा है जैसे म.प्र. में बाघों व चीता तेन्दुओं व पैंगोलिन की संख्या में बढ़ोत्तरी होने लगी है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. The Census is an important decadal exercise in the context of governance in India. Discuss. Also, highlight the impact of delay in the Census.

(150 words) 10

भारत में गवर्नेंस (अभिशासन) के संदर्भ में जनगणना एक महत्वपूर्ण दशकीय कार्य है। चर्चा कीजिए। साथ ही, जनगणना में विलंब के प्रभाव को रेखांकित कीजिए।

भारतीय जनगणना अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना आयोजित की जाती है किन्तु 2021 में होने वाली जनगणना में COVID-19 के कारण देरी देखी गई है।

अभिशासन के संबंध में जनगणना का महत्व

① आंकड़ों की उपलब्धता → प्रभावी व साक्ष्य आधारित नीति निर्माण हेतु
→ नीति क्रियान्वयन के प्रभाव हेतु

② पुराने सुभेद्य वर्गों की स्थिति में परिवर्तन तथा नवीन सुभेद्य वर्गों की पहचान हेतु
जैसे) LGBTQ वर्ग विकास की जानकारी।

③ वृहद स्तर पर नीति निर्माण के संचालन हेतु
जैसे) बेटी - बचाओ, बेटी पढ़ाओ मिशन लिंगानुपात सुधारने

④ जनसंख्या की संरचना, आवश्यकता समझने
जैसे) युवा जनसंख्या हेतु, कौशल विकास कार्यक्रम की आवश्यकता
बढ़े

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑤ देश के नागरिकों/~~निवासियों~~ की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का निर्धारण

जैसे) 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आँकड़े।

⑥ देश के नागरिकों व निवासियों के मध्य अंतर स्थापित करने

जैसे-) जनगणना के साथ National Population Register (NPR) की भी गणना।

विलम्ब के प्रभाव

- नीति निर्माण में बाधा
- आँकड़ों के परिवर्तन के आँकलन में समस्याएँ
- व्यय में बढ़ोत्तरी (जनगणना में होने वाला)
- सामाजिक व ~~आर्थिक~~ स्वास्थ्य संबंधी मानकों आदि में देरी से SDG लक्ष्य प्राप्ति में देरी की सम्भावना

जनगणना किसी भी राष्ट्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है सरकार को COVID-संबंधी मानकों के साथ जल्दी से जल्दी इसका क्रियान्वयन पूर्ण करना चाहिए।

———— x ———— x ————

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Broadly explain the composition and functions of the District Mineral Foundation (DMF). Also, discuss the issues in the effective utilisation of DMFs. **(150 words) 10**

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की संरचना और कार्यों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसके अतिरिक्त, DMFs के प्रभावी उपयोग में विद्यमान मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

जिला खनिज फाउंडेशन के जिला खनिज निधि से अधिकार वापस लिये जाने के आलोक में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

DMF की संरचना

- जिलाधीश
- ~~स्र~~ जिले के राजनीतिक प्रतिनिधि
- खदानों में कार्यरत मजदूरों के प्रतिनिधि

जिला खनिज फाउंडेशन के कार्य

(1) खनिज निधि में प्राप्त राशि का श्रमिकों के कल्याण, ~~सा अवसं~~ सामाजिक अवसंरचना सुधार पर व्यय।

(2) श्रमिकों की सुरक्षा का विनियमन।

(3) गौण खनिजों के उत्पादन संबंधी अनुमति प्रदान करना।

(4) सामाजिक आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित करना (खनन क्षेत्रों में)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

DMFs के प्रभावी उपयोग में विद्यमान मुद्दे

① खनिज निधि की एक बड़ी राशि अव्ययित रह गई।

② राजनीतिक उपकरण की तरह उपयोग।

③ आवंटित राशि का अनुत्पादक कार्यों में उपयोग।

④ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गये हैं।

इस संबंध में केन्द्र ने DMFs से खनिज निधि के अधिकार वापिस अपने पास स्थानांतरित कर लिये जिसका विभिन्न राज्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सरकार को विभिन्न सुधारों के साथ पुनः ये अधिकार हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. The SWAMITVA scheme has the potential to not only revitalise the Indian rural economy but empower rural people as well. Discuss.

(150 words) 10

'स्वामित्व' योजना में न केवल भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, अपितु इसमें ग्रामीण लोगों को भी सशक्त बनाने की क्षमता है। चर्चा कीजिए।

ग्रामीण क्षेत्र में भू- अभिलेखों को मान्यता देने व रिकार्ड का डिजीटलीकरण करने हेतु 'स्वामित्व योजना' का प्रारंभ किया गया है।

योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित

① भूमि विवादों की संख्या में कमी।

② सहकारी कृषि को बढ़ाने में सहायक।

③ भूमि के खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चमड़ा उद्योग) आदि को प्रोत्साहन।

④ विवाद के कारण परती भूमि पर पुनः खेती के प्रयासों से उत्पादन में वृद्धि।

⑤ सरकार के प्रयासों से चकबंदी हेतु भी सहायक हो सकती है।

⑥

योजना से ग्रामीण सशक्तीकरण

① विवादों में कमी से सामाजिक पूंजी का निर्माण।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② चकबंदी के लाभों का फायदा सभी को उपलब्ध हो सकेगा।

③ ~~ग्रामीण~~ भू संबंधी अभिलेखों की प्राप्ति से सरकारी कार्यालयों पर जवाबदेही व पारदर्शिता में वृद्धि।

④ ग्रामीण आपदा के समय मुआवजा, फसल बीमा आदि अधिकार सशक्ती से माँग सकेंगे।

⑤ ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक उद्योगों के विकास का लाभ सम्पूर्ण जनसंख्या को होगा।

स्वामित्व योजना सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है तथा इसमें वास्तविकता में ग्रामीण भारत में दीर्घकालीन बदलाव लाने की क्षमता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. In India's political system, the executive and legislature are not strictly separated, instead, their relationship is intimate and non-dichotomous. Comment. **(250 words) 15**

भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, कार्यपालिका और विधायिका को पूर्णतः पृथक नहीं किया गया है, अपितु इनके मध्य अभिन्न एवं अविच्छेद संबंध हैं। टिप्पणी कीजिए।

भारत की राजनीतिक व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित है जहाँ शक्ति पृथक्करण से अधिक महत्व नियंत्रण एवं संतुलन तथा जवाबदेही को दिया जाता है।

कार्यपालिका व विधायिका के मध्य अभिन्न व अविच्छेद संबंध

(1) कार्यपालिका के सभी सदस्यों को विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य (न होने पर 6 माह के भीतर)

(2) कार्यपालिका संवैधानिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। (अनुच्छेद-74)

(3) राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख। संसद का अंग है सभी ~~अधिनियम~~ उसी की स्वीकृति ~~से पारित~~ के पश्चात् विधि अधिनियम।

(4) राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति विधायिका में निहित है।

(5) बजट बनाना व संसद में पेश करना तथा पारित कराना कार्यपालिका का संवैधानिक दायित्व है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑥ (विधायिका) ~~सदस्यसभा~~ विभिन्न कटौती प्रस्तावों व CAG की रिपोर्ट के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।

⑦ ~~विधि~~ कार्यपालिका द्वारा किये ~~ख~~ गये विभिन्न संधि, समझौतों को विधायिका की अनुमति अनिवार्य है।

यद्यपि प्रभावी कार्यपालिका की स्थिति में कुछ विच्छेद दिखाई देते हैं

---

i) कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों का उपयोग कर विधायी प्रक्रिया को कमजोर किया जाता है।

ii) विधायिका की समितियों की शक्तियाँ कम की जाती हैं।

iii) लोकसभा ~~,~~ अध्यक्ष, सामान्यतः उसी दल से चुना जाता है ~~जिसके~~ जो दल कार्यपालिका का गठन करता है अतः संसद में नियम आदि बनाने में तटस्थता का पालन नहीं किया जाता है।

iv) सामान्य विधेयकों को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत करने तथा प्रश्नकाल स्थगित करने, बजट सत्र छोटा करने के ~~क~~ तरीकों का भी कार्यपालिका द्वारा उपयोग किया गया है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संविधान सभा द्वारा भारत में विधायिका व कार्यपालिका के समन्वय पर आधारित उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु प्रावधान निश्चित किये हैं थे अतः उन्होंने इस हेतु संसदीय व्यवस्था को चुना। संसदीय प्रणाली ने भारत में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अतः नियंत्रण व संतुलन को और अधिक प्रभावी बनाकर संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं को बनाए रखे जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. The idea behind deploying information and technology in government operations is to transform the way government works and reinvent people's participation in the democratic process. Discuss. **(250 words) 15**

सरकारी कार्य प्रणाली में सूचना एवं प्रौद्योगिकी को अपनाने के पीछे निहित विचार सरकार के कामकाज के तरीकों में बदलाव लाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को पुनःस्थापित करना है। चर्चा कीजिए।

भारतीय सरकारी कार्यप्रणाली को विश्व स्तर पर प्रायः धीमी व अनुत्तरदायी प्रक्रिया में देखा जाता है जिसमें बदलाव लाने हेतु सरकार शासन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है।

सरकार के कामकाज के तरीकों में बदलाव लाने की क्षमता

(A) कार्यों का स्वचालीकरण : i) अद्यतन सामग्री आधारित Back office support, विभिन्न कार्यों का Navigation आदि द्वारा।

ii) ई-फाइल संचालन, ई-संपर्क आदि से।

(B) कागजी कार्यवाही में कमी : iii) विभागों के मध्य E-संचार

iv) तीव्र गति से कार्य निष्पादन।

(C) प्रभावी सेवा वितरण –
- v) कार्यों का E-Access
- vi) Web द्वारा अधिकतम लोगों तक प्रसार।

(D) प्रभावी नीति निर्माण –
- vii) साक्ष्य आधारित
- viii) आकांक्षी जिला कार्यक्रम का संचालन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस प्रकार प्रौद्योगिकी द्वारा कार्यों में तीव्रता, न्यूनतम लागत व अधिक पहुँच के साथ संचालन किया जा सकता है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी में सुधार

i) सूचना तक लोगों की प्रभावी पहुँच उन्हें सशक्त बनाती है

ii) सार्वजनिक सूचना पर सार्वजनिक नज़र शासन को अधिक जवाबदेह व पारदर्शी बनाता है।

iii) नागरिक नीति निर्माण व नीति क्रियान्वयन पर स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकते हैं।

iv) राजनीतिक जवाबदेही :- सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा नागरिकों को राजनीतिज्ञों व प्रशासकों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं।

जैसे) E-टेण्डरिंग व्यवस्था में भ्रष्टाचार की न्यून संभावना

सूचना-प्रणाली उपयोग में समस्याएँ

① भारत में अभी भी विशाल वर्ग निरक्षर यहाँ तक कि शिक्षित वर्ग में भी डिजीटल निरक्षरता व भागीदारी को हतोत्साहित करती है।

② प्रशासन में प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव

③ • Digital Divide (ग्रामीण क्षेत्र में निम्न अवसंरचना)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

३ (५) राजनीतिक उदासीनता से और अधिक समस्या।
(६) गोपनीयता व सुरक्षा संबंधी मुद्दे।

वर्ल्ड ने बैंक ने अपनी रिपोर्ट
Data में कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी में शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने की व्यापक क्षमता है।
भारत सरकार को इन सभी चुनौतियों से निपटते हुए डिजिटल समावेशी व लोकतांत्रिक भारत के निर्माण पर पथ आगे बढ़ना चाहिए।

13. Do you agree that National Rural Livelihood Mission has become a truly transformative programme in addressing livelihood challenges in India? Discuss. **(250 words) 15**

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत में आजीविका की चुनौतियों से निपटने के लिए वास्तव में एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम बन गया है? चर्चा कीजिए।

स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना व आदि अन्य योजनाओं का एकीकरण कर 2014 में दीन दयाल - राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का प्रारंभ किया गया जो ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

ग्रामीण आजीविका की चुनौतियाँ (भारत में)

- निम्न कौशल
- निम्न उत्पादकता
- प्रच्छन्न बेरोजगारी
- निम्न महिला कार्यबल
- साख तक पहुंच नहीं

मिशन द्वारा ग्रामीण आजीविका की चुनौतियों का समाधान

(1) निम्न कौशल का समाधान

मिशन ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण में सहायता करता है व उन्हें उत्पादक गतिविधियों स्वरोजगार आदि में संलग्न करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② निम्न उत्पादकता

जिसका कारण 70% ग्रामीण आबादी का कृषि कार्यों में संलग्न होना है।

मिशन ग्रामीण लोगों को गैर-कृषि कार्यों, जैसे - खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उद्योग, वस्त्र निर्माण, लघु वनोपज उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित करने में सहायता करता है।

③ प्रच्छन्न बेरोजगारी

~~कृषि~~ कृषि क्षेत्र में जहाँ सीमान्त उत्पादकता शून्य

मिशन ग्रामीण युवाओं को डिजीटल शिक्षा, E-बैंक मित्र जैसे कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

④ महिला भागीदारी

महिला SHG के गठन ~~की~~ में सहायता तथा उन्हें सशक्त करना, प्रभावी निर्णय लेने में आगे बढ़ाना आदि माध्यमों द्वारा श्रमबल में शामिल करना।

⑤ SHG के माध्यम से साख व ऋण तक ग्रामीणों की पहुँच स्थापित की जा रही है ताकि इनका अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन हो तथा वे कार्यशील पूंजी तक पहुँच स्थापित कर सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) निम्न कुशल रोजगार - निम्न उत्पादकता - निर्धनता के दुष्चक्र को समाप्त ~~करके~~ कर ग्रामीण निर्धनता की समाप्ति का भी मिशन प्रयास कर रहा है।

मिशन से संबंधित समस्याएं

(1) अधिकारी तंत्र की निष्क्रियता।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त अशिक्षा, व सामाजिक रूढ़ियाँ जो महिलाओं को SHG में शामिल होने से रोकती हैं।

(3) मिशन में पर्याप्त डेटा का अभाव देखा गया है तथा योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर निर्मित नहीं किया जा रहा है।

(4) SHG से संबंधित समस्याएं मिशन की प्रभाविता को कम करती हैं।

* इन समस्याओं के निराकरण तथा प्रभावी निगरानी के साथ मिशन को ग्रामीण भारत में क्रियान्वित किया जाना आवश्यक ताकि एक समावेशी व समृद्धशाली व सशक्त भारत का निर्माण किया जा सके।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. The issuance of Citizens' Charters alone can not change the mindset of staff and clients overnight, rather, regular, untiring and persistent efforts are required to bring about attitudinal changes. Discuss. **(250 words) 15**

केवल सिटीजन चार्टर जारी करने से कर्मचारियों और ग्राहकों की मानसिकता में ऐकाएक परिवर्तित नहीं की जा सकता, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाने के लिए नियमित, अथक और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। चर्चा कीजिए।

सिटीज़न चार्टर किसी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं तथा सेवा प्राप्ति न होने की स्थिति में उपलब्ध तंत्र का विवरण है। असल में लगभग प्रत्येक विभाग द्वारा इसका निर्माण किया जाता है।

सिटीजन चार्टर का महत्व

(1) ग्राहक केन्द्रित प्रशासन की ओर बढ़ना

(2) प्रभावी सेवा वितरण।

(3) नागरिकों की अपेक्षाओं को समझना व उनकी पूर्ति करना।

(4) प्रभावी फीडबैक तंत्र उपलब्ध कराना।

(5) सेवा प्राप्तकर्ता को आने वाली समस्याओं का समाधान करना।

(6) प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता में वृद्धि करना।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिटीजन चार्टर से कर्मचारियों व ग्राहकों की मानसिकता में परिवर्तन का अभाव :-

(1) कर्मचारियों द्वारा पुरानी प्रक्रियाओं द्वारा कार्यों का संचालन
(2) चार्टर के बारे में जागरूकता का अभाव।
(3) उल्लंघन पर कोई विधिक दायित्व नहीं।
(4) चार्टर का समय पर updation नहीं।
(5) संस्थागत भ्रष्टाचार तथा इसकी सामाजिक स्वीकृति

जो मानसिकता परिवर्तन का सबसे बड़ा विरोधी है।

व्यवहार में बदलाव लाने हेतु प्रयास

(1) चार्टर को विधिक स्वरूप प्रदान करना तथा कर्मचारियों को जवाबदेही की ओर ले जाएगा।
(2) नागरिकों के मध्य बड़ा प्रचार-प्रसार अभियान का संचालन (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह)
(3) सरकारी कर्मचारियों को इस हेतु प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता ताकि मानसिकता में परिवर्तन हो।
(4) चार्टर के निर्माण की प्रक्रिया में जनभागीदारी लोगों को इस ओर आकर्षित करेगी।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) नागरिकों द्वारा प्राप्त Feedback पर अमल तथा और अधिक बेहतरी के प्रयास सरकार को उसके वास्तविक उद्देश्य पूर्ण रूप में सहायता प्रदान करेगा।

शासन में जवाबदेही व पारदर्शिता तभी सभी नागरिकों को मिलकर प्रयास करने होंगे चाहे वे शासन की ओर हों या नागरिकों की ओर, समन्वित प्रयास से ही भारत में Governance को Good Governance में बदला जा सकेगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Reduction in the overall size of the bureaucracy has been seen as the underlying idea behind civil services reforms. Is it a good idea to reduce the size of Indian bureaucracy? Examine in light of the experience of India.

(250 words) 15

नौकरशाही के समग्र आकार में कमी को सिविल सेवाओं में सुधार के पीछे अंतर्निहित विचार के रूप में देखा गया है। क्या भारतीय नौकरशाही के आकार को कम करना एक उपयुक्त विचार है? भारत के अनुभव के आलोक में परीक्षण कीजिए।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 13वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत में मंत्रालयों व विभागों की अधिकता को शासन में कमी के रूप में देखा गया है जिस हेतु विभिन्न विद्वान इनको कम कर सिविल सेवा / नौकरशाही को कम करने का विचार प्रस्तुत करते हैं।

आकार कम करने के कारण

i) सिविल सेवा पर होने वाला अत्यधिक व्यय।

ii) नौकरशाहों के मध्य समन्वय का अभाव।

iii) विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संघर्ष

iv) कम नौकरशाहों का प्रशिक्षण आसान।

v) सरकार की Maximum Governance और Minimum Government की नीति।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

यद्यपि आकार कम करने को सुधार के रूप में देखा जा रहा है किन्तु :-

① भारत में प्रति व्यक्ति सिविल सेवकों की संख्या G-20 देशों में सर्वाधिक कम है —

② ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के 28,000 पद रिक्त हैं।

इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएँ

① ~~नौकरशाह~~ भारत की विशाल आबादी तथा उसमें उपस्थित विशाल सुभेद्य वर्ग जो पूर्णतः सरकार पर निर्भर है
को सेवा वितरण कार्य नौकरशाहों द्वारा अ. जिसमें कमी से निश्चित रूप से वितरण में कमी।

② प्रशासनिक कार्यों की जटिल होती प्रकृति और मात्रा में नौकरशाहों की माँग करती है।

③ भारत के विशाल आकार व प्रशासन को ~~आकार~~ संभालने सि.सेवकों की आवश्यकता है।

④ नौकरशाह शासन की नीतियों को निरंतरता प्रदान करते हैं अतः कमी से प्रशासन में विभिन्न समस्याएँ खड़ी होंगी।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) II-ARC ने भी प्रशासन में सिविल सेवकों को बढ़ावा की अनुशंसा की है।

अतः सिविल सेवाओं में सुधार हेतु नौकरशाही क्रम करने को नहीं परिवर्तित करने की आवश्यकता है उन्हें नियम आधारित प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन की ओर ले जाने की जिसमें मिशन कर्मयोगी जैसे कार्यक्रम प्रभावी सिद्ध होंगे अतः सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Diseases and outbreaks are realities and a well-functioning system can help reduce their impact. Discuss the relevance of a future ready disease surveillance system for India. **(250 words) 15**

रोग और प्रकोप वास्तविकताएं हैं तथा एक सुचारू रूप से कार्य करने वाली प्रणाली उनके प्रभाव को कम करने में सहायता कर सकती है। भारत में, आगे आने वाले समय के लिए एक रोग निगरानी प्रणाली की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।

विज्ञान के अनुसार प्रकृति अपना संतुलन स्थापित करने के रास्ते खोज लेती है इसी रूप में जलवायु परिवर्तन व प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास ने विभिन्न रोग व प्रकोपों में वृद्धि की है जिसका उदाहरण COVID-19 के पश्चात ब्लैक फंगस का प्रभाव तथा मंकीपॉक्स जैसी बीमारियाँ हैं।

सुचारु प्रणाली द्वारा रोगों के प्रबंधन में सहायता

i) बीमारी की पहचान हेतु तंत्र उपलब्धता।

ii) बीमारी के प्रसार की क्षमता, प्रभावित क्षेत्र तथा प्रभावित जनसंख्या का आंकलन।

iii) तीव्रता से प्रसार की स्थिति में पूर्व निर्धारित प्रक्रियाएँ। [कंटेनमेंट जोन, lock down आदि]

iv) रोगियों की पहचान तथा स्वास्थ्य अवसंरचना को तैयार बनाये रखना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

v) प्रभाव को सीमित क्षेत्रों तक रोकना।

vi) संसाधनों का तीव्रता से प्रबंधन व क्षमता निर्माण
[COVID-19 के समय O_2 की कमी देखी गई]

vii) प्रतिक्रिया हेतु संघ व राज्यों के मध्य आवश्यक सहयोग की रूपरेखा निर्धारित करना।

भारत में रोग निगरानी प्रणाली की प्रासंगिकता

COVID-19 के समय आने वाली समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में इन्हें देखा जा सकता है:-

① रोग की व्यापकता का आंकलन: COVID-19 की सूचना भारत में ~~किन्तु Lockdown का निर्णय~~ आंकलन में देरी से Lockdown में देरी।

② विशाल आबादी:- निगरानी, प्रबंधन व जांच की निश्चित प्रणाली के पूर्व निर्धारण की आवश्यकता।

③ अत्यधिक विविधता:- विभिन्न ~~जीनोमो~~ जीनोमो की उपस्थिति रोगों के अलग-अलग प्रभाव को प्रदर्शित कर सकती है।

④ अधिक जनसंख्या घनत्व:- जहाँ निगरानी के बिना किसी संक्रामक रोग का प्रसार तीव्रता से।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑤ सुभेद्य वर्गों की उपस्थिति : अत्यधिक संख्या जिन पर बीमारी का प्रभाव दीर्घकालिक।

⑥ निम्न स्वास्थ्य अवसंरचना : जो बीमारी होने के पूर्व ~~निगरानी व~~ उसे रोकने हेतु बाध्यता आरोपित करती है।

यद्यपि चेतावनी प्रणाली एक अच्छी पहल साबित होगी किन्तु उसके आने वाले भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने भारत को अपना स्वास्थ्य व्यय बढ़ाकर स्वास्थ्य अवसंरचना होने को मजबूत करना अत्यावश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. It is imperative to conceive a system that allows fair admission process in medical colleges while preserving merit and preventing rampant commercialisation. Critically examine the statement in the context of opposition to National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) by some states. **(250 words) 15**

एक ऐसी प्रणाली पर विचार करना अनिवार्य है जो योग्यता को संरक्षित करते हुए और बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण को रोकते हुए मेडिकल कॉलेजों में निष्पक्ष प्रवेश प्रक्रिया की अनुमति दे। कुछ राज्यों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) के विरोध के संदर्भ में, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

राष्ट्रीय पात्रता - सह प्रवेश परीक्षा

सम्पूर्ण भारत में मेडिकल कॉलेजों में डाक्टरी (BAMS, BHMS, MBBS) की पढ़ाई में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा है।

राज्यों द्वारा NEET का विरोध करने के कारण

1. स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय जबकि परीक्षा का आयोजन केन्द्र द्वारा।
2. पेपर की क्षेत्रीय भाषा में अनुपलब्धता।
3. राज्यों को अपने विद्यार्थियों के पिछड़ने का डर।
4. अपनी अपनी अवसंरचना पर अन्य राज्य के विद्यार्थियों के उपयोग का विरोध [तमिलनाडु द्वारा]

योग्यता को संरक्षित व व्यवसायीकरण को रोकने निष्पक्ष प्रवेश प्रक्रिया की आवश्यकता

① कोचिंगों का बढ़ता प्रचलन : इस प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंगों का प्रचलन बड़ी समस्या उत्पन्न करता है।

② मेडिकल कॉलेजों द्वारा NRI कोटे आदि का अयोग्य समाप्त करने की आवश्यकता।

③ प्रवेश परीक्षा के बिना प्रवेश को रोकना।

④ सभी राज्यों की समान भागीदारी व समान क्षमता के अनुसार परीक्षा का आयोजन।

NEET द्वारा समाधान

① पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया है तथा सभी विद्यार्थियों का समान आँकलन।

② इस परीक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम द्वारा प्रवेश पर रोक।

③ विभिन्न भाषाओं में पेपर का प्रकाशन।

④ All India कोटे का उचित वितरण का ध्यान।

⑤ गुणवत्ता पूर्ण प्रश्न पत्र तथा पारदर्शी प्रणाली व जवाबदेह प्रक्रिया।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

NEET एक सफल परीक्षा है

केन्द्र-राज्यों को एक समान मंच पर बैठना जैसे होने वाली समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। यद्यपि भारत में स्वास्थ्य प्रणाली में एकरूपता हेतु एक अखिल भारतीय परीक्षा अनिवार्य है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. 15 years of the Right to Information Act have thrown up multiple experiences, some of which need to be built upon, while others necessitate steps to uphold the act in its letter and spirit. Explain with examples.

(250 words) 15

सूचना का अधिकार अधिनियम के 15 वर्षों ने अनेक अनुभव प्रदान किए हैं, जिनमें से कुछ को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जबकि अन्य में अधिनियम को अपने सिद्धांत और भावना में बनाए रखने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

नागरिक समाज द्वारा नेतृत्वित आंदोलन के फलस्वरूप 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। जो नागरिकों को किसी भी विभाग (कुछ अपवाद के साथ) सूचना प्राप्त करने का कानूनी विधिक अधिकार प्रदान करता है।

अधिनियम के अनुभव

- पारदर्शिता में वृद्धि (राजस्थान में जन सूचना पोर्टल)
- भ्रष्टाचार का खुलासा (मध्यप्रदेश में व्यापम घोटाला)
- जनसहभागिता में वृद्धि (RTI आवेदनों की बढ़ती संख्या)
- प्रशासन में सुधार (विभिन्न स्तरों के जन अधिकार अधिनियम)

अनुभव जिन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता

i) स्वतः प्रकटीकरण :- धारा-4 के अनुपालन में विभागों को राजस्थान के उदाहरण का पालन जहाँ पोर्टल पर सूचनाओं का स्वतः प्रकटीकरण।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ii) जन सहभागिता में वृद्धि :- अधिनियम का अधिक प्रचार-प्रसार कर ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना जहाँ पंचायत अभी भी पारदर्शिता से दूर बनी हुई है। (ग्रामीण निरक्षरता के कारण)

iii) प्रशासन में सुधार :- अधिनियम को प्रभावी बनाने स्वत: नवाचार करना

iv) अधिनियम को उसकी मूल भावना के साथ लागू करना।

क्षेत्र जहाँ कदम उठाने की आवश्यकता

(1) सूचना आयोगों व आयुक्तों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से RTI अधिनियम में 2019 के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में।

(2) आयुक्तों की अधिक संख्या में नियुक्ति अभी रिक्त पद खाली।

(3) राजनीतिक दलों को न्यायपालिका, दैनिक प्रक्रियाओं को अधिनियम के अंतर्गत लाना।

(4) आयोग के वेतन भत्तों को संचित निधि पर भारित करना।

(5) शासकीय गोपनीयता अधिनियम - 1923 का उपयोग सीमित करना।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सूचना वह माध्यम है जो नागरिकों को सशक्त बनाकर शासन में जनसहभागिता में वृद्धि करता है जिससे ~~प्रशासन~~ अंततः लोकतंत्र मजबूत होता है। RTI अधिनियम में आवश्यक सुधार कर सरकार को भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. There is a need to ensure better ethical standards, accountability and management of temples in India. Discuss in the context of issues associated with state intervention in management of temples. **(250 words) 15**

भारत में मंदिरों के बेहतर नैतिक मानकों, जवाबदेही और प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मंदिरों का संचालन धार्मिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है किन्तु भारत की सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता नैतिक मानकों, जवाबदेही व प्रबंधन सुनिश्चित करने प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकती है।

राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता

नैतिक मानक

① भ्रष्टाचार व दान के कुप्रबंधन के आरोप।

② मंदिरों के बाहर भिखारियों की बढ़ती संख्या।

जवाबदेही

③ मंदिरों के दान को करों से छूट उन्हें संचालित करने वालों को गलत कार्य करने आकर्षित करती है।

④ मंदिरों को सरकार व अंतिम रूप से नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने।

प्रबंधन

⑤ मंदिरों में बढ़ती भगदड़ की घटनाएँ (हाल में वैष्णोदेवी में)

Call us : 8468022022, 9019066066 Visit us : www.visionias.in

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) विशाल मात्रा में श्रद्धालुओं का आगमन तथा मंदिरों के पास प्रशिक्षित अमलल का अभाव।

राज्य के हस्तक्षेप संबंधी मुद्दे

(1) धार्मिक स्वतंत्रता के आधार के विरुद्ध।

(2) धर्म निरपेक्षता के आधार राज्यों को प्रबंधन से दूर रहना चाहिए।

(3) सामान्यतः प्रबंधन इन्हीं द्वारा किया जाता है जो संभालने में समर्थ।

(4) राज्य प्रथाओं को संवैधानिक नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में देखता है जबकि श्रद्धालु धार्मिक अतः संघर्ष का जन्म हो सकता है।

निश्चित नियमों के पालन में राज्य को प्रबंधन हाथ में लेना चाहिए किन्तु यह प्रबंधन मानव संसाधन तथा अन्य संसाधनों के प्रबंधन तक सीमित होना चाहिए। धार्मिक प्रथाओं के प्रबंधन या

हस्तक्षेप से राज्य को स्वयं को रोकना चाहिए।

20. India continues to be a country with one of the highest shortages of skilled workforce. Discuss the reasons and remedies for this scenario.

(250 words) 15

भारत कुशल कार्यबल की सर्वाधिक कमी वाला देश बना हुआ है। इस परिदृश्य के लिए उत्तरदायी कारणों और उपायों पर चर्चा कीजिए।

ICE 360° रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कार्यबल में कुशल कार्यबल की संख्या मात्र 5% है जो चीन के 24% तथा जर्मनी के 80% की संख्या में अत्यंत कम है।

कुशल कार्यबल में कमी के कारण

Ⓐ शैक्षिक कमी
- (1) शिक्षा का निम्न स्तर
- (2) समान पाठ्यक्रम
- (3) उच्च Drop out Rate
- (4) कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अभाव

Ⓑ महिला सहभागिता
- (5) मात्र 20%
- (6) विभिन्न सामाजिक आर्थिक प्रभाव जिनका मुख्य कारण पितृसत्तात्मकता

Ⓒ उद्योग - शिक्षा का निम्न जुड़ाव
- अप्रचलित पाठ्यक्रम
- भारत में शिक्षित नियोजनीयता 50% से कम

Ⓓ

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(1) निजी क्षेत्र की भूमिका → भागीदारी नहीं
→ भागीदारी वाले क्षेत्र शहरों व अत्यधिक महंगे।

सुधार के उपाय

(1) आधारभूत शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव
जैसे→ नई शिक्षा नीति द्वारा अभिकल्पना।

(2) विशाल कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन।
जैसे→ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।

(3) शिक्षा - उद्योग जुड़ाव को बेहतर करना।

(4) कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन।

(5) कौशल प्रदाता व रोजगार मांगकर्ता के मध्य जुड़ाव।

(6) महिला सशक्तिकरण व महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में आने के अवसर प्रदान करना।
जैसे→ प्रतिभा किरण योजना।

(7) निजी क्षेत्र को आगे आने के अवसर प्रदान करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(8) शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन।

WTO के अनुसार भारत कौशल विकास द्वारा 2035 तक अपनी GDP में 3-5% तक की वृद्धि कर सकता है इसके विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश को भुनाने हेतु भारत को तेजी से कौशल प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है।